नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 232
दि. 26.05.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनटीए की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी पेपर लीक मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और सरकारी जवाबदेही को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बार-बार सामने आ रही परीक्षा गड़बड़ियों से यह साफ है कि एजेंसी ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। अदालत की सख्त टिप्पणियों के बाद एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता कटघरे में आ गई है। न्यायमूर्ति P. S. Narasimha और न्यायमूर्ति Aalok Araadhe की पीठ इस मामले से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पहले भी पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मामले सामने आने के बावजूद पर्याप्त सुधार नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि यह मामला पहली बार उसके सामने नहीं आया है। पूर्व में भी परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई थीं। उस समय अदालत ने एक विशेष समिति गठित कर परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए कई सुझाव दिए थे। इन सुझावों में डिजिटल सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ट्रांसमिशन व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और डेटा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण उपाय शामिल थे। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन सिफारिशों के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ और एक बार फिर लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया। न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को निर्देश दिया कि वह गुरुवार तक विस्तृत हलफनामा दाखिल कर बताए कि पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों और निगरानी समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने केंद्र सरकार और Central Bureau of Investigation (सीबीआई) से भी जवाब तलब किया है। अदालत यह जानना चाहती है कि इतने बड़े स्तर पर आयोजित परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था बार-बार कैसे विफल हो रही है और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी।

मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (फाइमा) ने भी सर्वोच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की है। संगठन ने मांग की है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए मौजूदा व्यवस्था की जगह एक स्वतंत्र, मजबूत और अत्याधुनिक परीक्षा प्रणाली विकसित की जाए। फाइमा का कहना है कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है। संगठन ने अदालत से कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम और मानसिक दबाव के बीच परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और भविष्य दोनों को प्रभावित कर देती हैं।

फाइमा ने यह भी मांग की है कि जब तक नई और विश्वसनीय व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति बनाई जाए। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, फोरेंसिक विशेषज्ञ और शिक्षा प्रशासन से जुड़े अनुभवी अधिकारियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। संगठन का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि तकनीकी स्तर पर भी गंभीर खामियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए स्वतंत्र और विशेषज्ञ निगरानी जरूरी है।

इसी बीच यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने भी अदालत में अलग याचिका दाखिल कर एनटीए की मौजूदा संरचना को भंग करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी लगातार विवादों में घिरती जा रही है और अब छात्रों का उस पर भरोसा कम होता जा रहा है। संगठन ने सुझाव दिया कि देश में एक नई राष्ट्रीय परीक्षा संस्था बनाई जाए, जो पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था के तहत कार्य करे। उनका कहना है कि मेडिकल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की प्रवेश परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही देश की भावी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है।

अब जानिए पूरा मामला क्या है। इस वर्ष नीट-यूजी परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में लगभग 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो गई। परीक्षा समाप्त होने के कुछ दिनों बाद विभिन्न राज्यों से पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने लगीं। सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्रों के कथित स्क्रीनशॉट और उत्तर साझा किए जाने के दावे भी सामने आए, जिसके बाद विवाद तेजी से बढ़ गया।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में अनियमितता की सूचना मिली थी। इसके बाद मामले को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जांच में कथित पेपर लीक नेटवर्क और संगठित गिरोह की गतिविधियों के संकेत मिलने के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की गई। 15 मई को शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने आधिकारिक रूप से 21 मई को री-एग्जाम कराने की तारीख घोषित की।

पेपर लीक विवाद के बाद देशभर में छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी गई। कई राज्यों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि वर्षों की मेहनत और प्रतियोगी तैयारी के बाद यदि परीक्षा प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए तो प्रतिभा और परिश्रम का महत्व खत्म हो जाता है। अभिभावकों ने भी सवाल उठाया है कि जब देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती तो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता के दावे कैसे किए जा सकते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ परीक्षा सुरक्षा को भी उसी स्तर पर मजबूत करना होगा। केवल प्रशासनिक निगरानी पर्याप्त नहीं है, बल्कि डिजिटल एन्क्रिप्शन, एआई आधारित निगरानी, साइबर ऑडिट और सुरक्षित प्रश्नपत्र वितरण प्रणाली जैसे उपायों को अनिवार्य बनाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब पूरे देश की नजर एनटीए, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है। यह मामला केवल एक परीक्षा के पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और युवाओं के भविष्य में जनता के भरोसे की बड़ी परीक्षा बन चुका है।

गुलमर्ग गोंडोला में तकनीकी खराबी से हवा में फंसे 300 पर्यटक, सेना और राहत दल का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया, जब दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे केबल कार सिस्टम Gulmarg Gondola में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। दोपहर करीब 2:30 बजे रोपवे के संचालन के दौरान सभी केबिन बीच हवा में ही रुक गए, जिससे 300 से अधिक पर्यटक ऊंचाई पर फंस गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

यह घटना गुलमर्ग के उस रोपवे सिस्टम में हुई जो पर्यटकों को बर्फीली पहाड़ियों और ऊंचे पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अचानक केबल कार रुक जाने से 65 केबिन हवा में लटक गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित बड़ी संख्या में पर्यटक सवार थे। हर केबिन में औसतन छह लोगों के बैठने की क्षमता होती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।

घटना के तुरंत बाद कई पर्यटक घबराहट में चीखते-चिल्लाते नजर आए, जबकि कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाते रहे। ऊंचाई पर फंसे लोगों

के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल बना रहा। मौसम और ऊंचाई के कारण स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई, हालांकि किसी प्रकार की चोट या गंभीर दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है।

सूचना मिलते ही भारतीय सेना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें मौके पर पहुंचीं और संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। राहत दल ने रस्सियों, सुरक्षा हार्नेस और अस्थायी सीढ़ियों की मदद से लोगों को एक-एक कर सुरक्षित नीचे उतारना शुरू किया। अब तक लगभग 16 केबिनों से करीब 80 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि शेष लोगों को निकालने का अभियान देर रात तक जारी रहने की संभावना है।

रेस्क्यू अभियान में सबसे बड़ी चुनौती ऊंचाई, ठंडी हवाएं और केबिनों की स्थिति बनी हुई है। बचाव दल अत्यधिक सावधानी के साथ काम कर रहा है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। सेना के जवान लगातार केबिन तक पहुंच बनाकर पर्यटकों को सुरक्षित हार्नेस के जरिए नीचे ला रहे हैं।

Gulmarg Gondola को दो चरणों में संचालित किया जाता है। पहला चरण गुलमर्ग को कोंगडोरी से जोड़ता है, जबकि दूसरा चरण कोंगडोरी से अफरवात पीक तक जाता है। यह एशिया के सबसे ऊंचे और सबसे लोकप्रिय रोपवे सिस्टम में से एक माना जाता है, जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी कुल क्षमता और ऊंचाई इसे साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्रों में शामिल करती है।

श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है और यह क्षेत्र सर्दियों में बर्फीली वादियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी कारण यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। सोमवार की घटना ने एक बार फिर ऐसे ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। विशेषज्ञ टीम को जांच के लिए लगाया गया है, जो यह पता लगाएगी कि रोपवे के संचालन में अचानक रुकावट क्यों आई। फिलहाल प्राथमिकता सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित नीचे लाना है।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और बचाव अभियान पूरी सावधानी के साथ जारी है। साथ ही पर्यटकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और रेस्क्यू टीमों के निर्देशों का पालन करें।

यह घटना भले ही बड़े हादसे में नहीं बदली, लेकिन इसने एक बार फिर पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियों को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।

सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर अमित शाह का बड़ा दौरा, बीएसएफ जवानों से करेंगे सीधा संवाद

नई दिल्ली। देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा बदलते सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah सोमवार रात से सीमावर्ती राज्यों के व्यापक दौरे पर निकल रहे हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार सीमा प्रबंधन, घुसपैठ रोकथाम और आंतरिक सुरक्षा समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान गृह मंत्री जमीनी स्तर पर सुरक्षा तंत्र की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को और प्रभावी बनाने पर जोर देंगे।

इस दौरे की शुरुआत राजस्थान से होगी, जहां गृह मंत्री बीकानेर पहुंचेंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, Rajasthan में पहुंचने के बाद वह 26 मई को भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है और यहां Border Security Force (बीएसएफ) के जवान चौबीसों घंटे निगरानी में तैनात रहते हैं। शाह इस दौरान जवानों से सीधे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और सीमावर्ती परिस्थितियों में उनके

कार्य अनुभवों की जानकारी लेंगे।

इस दौरे का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाना भी है। गृह मंत्री जवानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत और समीक्षा भी कर सकते हैं, जिनका उद्देश्य कठिन भौगोलिक और मौसमीय परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे सुरक्षा कर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि सीमाओं पर तैनात जवानों की कार्य परिस्थितियों में सुधार से देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।

बीकानेर में इस दौरान एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, बीएसएफ के शीर्ष अधिकारी और सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से सीमा पार से आने वाले खतरों, घुसपैठ रोकथाम, तस्करी, ड्रोन गतिविधियों और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार का फोकस अब सीमावर्ती क्षेत्रों में तकनीकी निगरानी बढ़ाने पर भी है। इसमें ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, स्मार्ट सर्विलांस, और रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे उपायों को मजबूत करने की योजना शामिल है। बदलते सुरक्षा खतरे और आधुनिक तकनीक के उपयोग को देखते हुए सीमा सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है।

राजस्थान के बाद गृह मंत्री का दौरा गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी प्रस्तावित है। इन राज्यों में भी वह स्थानीय प्रशासन, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक राज्य में सीमाओं की प्रकृति अलग होने के कारण सुरक्षा चुनौतियां भी भिन्न हैं, ऐसे में यह दौरा व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा केवल औपचारिक समीक्षा नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित, तकनीकी रूप से उन्नत और समन्वित सुरक्षा ढांचे में बदलने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में इस दौरे से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्णय भी सामने आ सकते हैं।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस दौरे के बाद सीमा सुरक्षा को लेकर कौन-कौन से नए कदम उठाए जाते हैं और जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था में कितना सुधार देखने को मिलता है।

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर, एआईएडीएमके में बगावत से मचा सियासी तूफान

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (एआईएडीएमके) के तीन बागी विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। ये विधायक पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रहे आंतरिक संघर्ष और नेतृत्व विवाद के बीच अलग रास्ता अपनाते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये तीनों विधायक जल्द ही मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay की पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam (टीवीके) में शामिल हो सकते हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल एआईएडीएमके की राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा भी तेज कर दी है।

सोमवार को एआईएडीएमके के तीन विधायकों—मदुरंतकम से मरगाथम कुमारवेल, धारापुरम से सत्यभामा और पेरुंदुरई से जयकुमार—ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष J. C. D. Prabhakar से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये तीनों विधायक

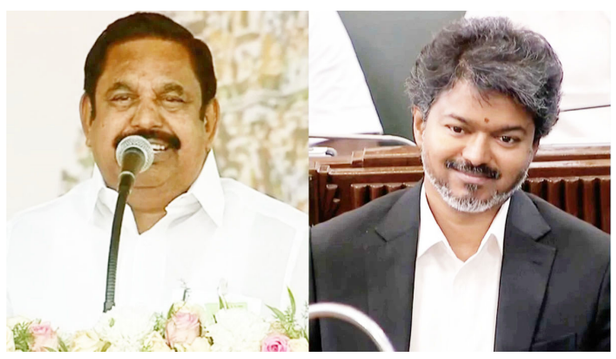

पार्टी के वरिष्ठ नेता C. V. Shanmugam और एस पी वेलुमणि के नेतृत्व वाले बागी गुट का हिस्सा माने जा रहे थे। विधानसभा सचिवालय में इस्तीफा सौंपने के तुरंत बाद ये विधायक टीवीके सरकार में मंत्री आधव अर्जुना से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, जिससे उनके टीवीके में शामिल होने की अटकलों को और बल मिला।

विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों विधायकों का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में उपचुनाव की तैयारियों और सत्ता समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब मदुरंतकम, धारापुरम और पेरुंदुरई सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसके अलावा त्रिची ईस्ट सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसे मुख्यमंत्री विजय ने दूसरी सीट बरकरार रखने के कारण खाली किया था।

इन इस्तीफों के बाद एआईएडीएमके की विधानसभा में संख्या 47 से घटकर 44 रह गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल संख्या में कमी नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर गहराते संकट का संकेत है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में नेतृत्व को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री विजय के विश्वास मत के दौरान यह असंतोष खुलकर सामने आ गया था, जब सीवी शनमुगम के नेतृत्व में पार्टी के 25 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया था।

टीवीके सरकार के पास उस समय 119 विधायकों का समर्थन था, लेकिन फ्लोर टेस्ट में उसे 144 वोट मिले थे। इसके बाद से ही एआईएडीएमके में राजनीतिक खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पार्टी महासचिव Edappadi K. Palaniswami ने बागी नेताओं पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया, जबकि शनमुगम गुट ने पलानीस्वामी द्वारा नियुक्त व्हिप की वैधता पर ही सवाल उठा दिए। इससे पार्टी के भीतर गुटबाजी और गहरी हो गई।

तमिलनाडु की राजनीति में इस घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को भी सक्रिय कर दिया है। Dravida Munnetra Kazhagam (डीएमके) ने टीवीके पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष विधायकों की खरीद-फरोख्त कर रहा है। डीएमके नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक दबाव और प्रलोभन देकर विपक्षी विधायकों को तोड़ा जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि टीवीके की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

एआईएडीएमके को इससे पहले भी बड़ा झटका लग चुका है। 18 मई को पार्टी के वरिष्ठ नेता एस सेम्मलाई ने भी इस्तीफा देकर संगठन की स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि चुनाव के बाद पार्टी में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उससे उन्हें गहरा मानसिक कष्ट हुआ है। सेम्मलाई ने कहा कि केवल वह ही नहीं, बल्कि पार्टी के लाखों कार्यकर्ता भी मौजूदा हालात से दुखी और निराश हैं। उनके इस्तीफे ने यह संकेत दे दिया था कि पार्टी के भीतर असंतोष केवल कुछ विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी गहराता जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभिनेता से राजनेता बने मुख्यमंत्री विजय की लोकप्रियता और टीवीके के तेजी से उभरने से तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द-गिर्द घूमने वाली राज्य की राजनीति अब नए राजनीतिक केंद्र की ओर बढ़ती दिख रही है। टीवीके का विधानसभा में बढ़ता प्रभाव विपक्षी दलों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि एआईएडीएमके के भीतर जारी असंतोष को जल्द नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में पार्टी को और बड़े राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं टीवीके के लिए यह घटनाक्रम राजनीतिक विस्तार और संगठनात्मक मजबूती का अवसर बन सकता है।

अब तमिलनाडु की राजनीति की नजर आगामी उपचुनावों, संभावित दल-बदल और एआईएडीएमके नेतृत्व की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण आने वाले महीनों में और बड़े उलटफेर का संकेत दे रहे हैं।

संपादकीय

दीर्घकालीन नीतियों से थमेगा गिरना

यूं देश के आयात-निर्यात असंतुलन के चलते पिछले दो दशकों से रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट देखी गई है, लेकिन हाल के कुछ महीनों में इस गिरावट में तेजी आई है। खासकर ईरान-अमेरिकी युद्ध शुरू होने के बाद इसमें छह फीसदी की चिंताजनक गिरावट आई है। जो हमारी आयात पर अत्यधिक निर्भरता को ही दर्शाता है। यद्यपि दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऐसे मुद्रा संकट कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया गिरावट हमारी चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल, यह गिरावट भू-राजनीतिक अस्थिरता, कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता से मुद्रास्फीति और धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि के बीच हो रही है। इन दबावों ने मिलकर एक ऐसा संवेदनशील वातावरण बनाया है, जिसमें रुपये की कमजोरी व्यापक आर्थिक व्यवधानों को जन्म दे रही है। वैसे तो बढ़ता आयात असंतुलन ही रुपये की गिरावट के मूल में है। सबसे बड़ा संकट तो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता का है, जो करीब ८८ फीसदी है। इसके अलावा खाद्य तेल, उर्वरक आदि आवश्यक वस्तुओं का आयात लगातार बढ़ा है। वहीं रुपये के डॉलर के मुकाबले लगातार गिरने से ये वस्तुएं महंगी हो गई हैं। खासकर ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर परिवहन, मालभाड़ा वृद्धि, भोजन और घरेलू खर्चों पर पड़ा है। इसके चलते रुपये के अवमूल्यन से कंपनियां तथा देश के नीति-निर्माता भी खासे चिंतित हैं। विदेशी मुद्रा में ऋण लेने वाली भारतीय कंपनियों पर ऋण चुकाने का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। दरअसल, इन सभी कारणों से बढ़ते व्यापार घाटे का चालू खाते के घाटे पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। जिसके चलते शेयर बाजार में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखा जा रहा है। वास्तव में विदेशी निवेशक अनिश्चितता के वातावरण में सुरक्षित अमेरिकी कंपनियों में निवेश बढ़ा रहे हैं। फलतः अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश में लगातार निकासी का रुझान देखा जा रहा है। जिसने हमारी आर्थिक चिंताओं को और बढ़ाया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस जारी अस्थिरता को कम करने के लिये विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से हस्तक्षेप किया है, लेकिन ऐसे उपाय महज गिरावट की गति को कम करने के अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने तर्क दिया है कि रुपये का स्वाभाविक रूप से अवमूल्यन करने से समय के साथ व्यापार असंतुलन को दुरुस्त करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने केंद्रीय बैंक से आग्रह किया है कि वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के कारण होने वाले मुद्रा के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिये विशिष्ट विनिमय दर लक्ष्यों मसलन सौ रुपये प्रति डॉलर से आगे बढ़कर विचार करना चाहिए। हालांकि, अनियंत्रित अवमूल्यन से गंभीर जोखिम भी पैदा हो सकते हैं। देश के नीति-निर्माताओं को बाजार समायोजन की अनुमति देने और अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के बीच सावधानी से संतुलन बनाने की जरूरत होगी। निश्चित रूप से सरकार की ओर से मुद्रास्फीति का कुशल प्रबंधन और अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा बनाये रखना, देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकता है।

अपने भू-राजनीतिक केंद्र की ओर लौटता भारत

“ भारत अपने पुराने भू-राजनीतिक केंद्र की ओर लौट रहा है। क्वाड देशों के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं वहीं ब्रिक्स समिट भी यहीं होनी है। विश्व कूटनीति में यह दौर 'मल्टी एलाइनमेंट' का है। एक साथ कई संबंधु साधना व संतुलन बनाना। हालांकि इस प्रक्रिया में चुनौतियां बहुत हैं, पिछले ढंग छोड़ने से गहरी दरारें बनी व संबंध तनावपूर्ण हुए।

खबरें स्वागत योग्य है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे- खासकर क्वाड गुट के विदेश मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में, जिसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी राजधानी पहुंचे हैं। अगले कुछ दिनों में होने वाला भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन दुर्भाग्यवश टालना पड़ा क्योंकि इबोला वायरस का खतरा फिर से सिर उठाने लगा है।

आखिरकार, भारत अपने पुराने भू-राजनीतिक केंद्र की ओर लौटता दिखाई दे रहा है। शायद इसके पीछे डोनाल्ड ट्रम्प का पाकिस्तान के प्रति छिपाए न छिपने वाला लगाव, पश्चिम एशिया में युद्ध से अर्थव्यवस्था पर चोट, और अमेरिका-चीन के बीच संभावित प्रलंयकारी तनाव ही वे वजहें थीं, जिन्होंने ध्यान केंद्रित करवाया। आखिरकार यह हो रहा है - भले ही विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सिबी जॉर्ज ने एक युवा नॉर्वेजियन पत्रकार को भारत की प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर लंबा-चौड़ा भाषण दिया हो, सिर्फ इसलिए कि उस पत्रकार ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया था, जो उन्हें नागवार लगा। यह छोटी सी कीमत है, जो चुकानी पड़ रही है। सच तो यह है कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, लूला दा सिल्वा, सिरिल रामाफोसा और नरेंद्र मोदी - ये सभी कुछ ही महीनों में एक वार्ता कक्ष में मौजूद होंगे। ये सब चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत के नेता हैं, जो ब्रिक्स संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। क्वाड गुट के विदेश मंत्रियों की बैठक इसका संकेत है कि लंबे समय से टलता आ रहा क्वाड शिखर सम्मेलन भी जल्द ही हो सकता है। यह इस बात का पैमाना है कि चीजें कितनी बदली हैं भले ही वे पहले जैसी न हों, पिछले 12 वर्षों में, जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, भारत की विदेश नीति की असली कहानी यही रही है। भारत ने अमेरिका (जिसके साथ रिश्ते आजकल जरा उतार-चढ़ाव भरे हैं), इस्राइल और यूएई के साथ दोस्ती प्रगाढ़ की है; गलवान की ठंडी-बर्फीली चोटियों पर चीन के साथ आमने-सामने की स्थिति बनी; पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन सीमा पार से जारी आतंकवाद के लिए उसे दंडित भी किया; अपने पड़ोस के अन्य भागों (जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका) के साथ रिश्तों को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की; और नीदरलैंड्स के साथ बराबर की हिस्सेदारी बनाई है। जहां तक नॉर्वे की बात है, तो हम यह जान चुके हैं कि छह अक्षरों के इस नाम में यदि वर्णमाला का 18वां अक्षर हटा दें तो बेहतर तरीके से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि कोई नया अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बनने वाला है। पिछले से पिछले हफ़्ते बीजिंग में ट्रंप का दौरा हमें बताता है कि चीन अमेरिकियों से टकराव करने से बचता रहेगा, क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। वहीं, गत सप्ताह बीजिंग में पुतिन के दौरे से पता चलता है कि यूक्रेन के साथ अपने गतिरोध वाले युद्ध के चौथे साल में, और पश्चिमी देशों के छिद्र-दार प्रतिबंधों की मदद से, रूस अहम संबंधों,जैसे कि चीन और भारत, को स्थिर रखने की कोशिशें जारी रखेगा। (रूस को पता है कि अमेरिका के साथ चीन के आर्थिक रिश्ते, रूस के प्रति चीन के रवैये को सीमित रखेंगे, भले ही दोनों देश अन्य मामलों पर कितनी भी सहमति क्यों न रखते हों)।

चलिए, हम इस दौर का नाम 'नए दोस्त तलाशने और लोगों को प्रभावित करना' रख देते हैं- यहां तक कि वे समाज के उच्च वर्ग यानी संभ्रांत तबके के लोग भी जो देशों को चलाने का काम करते हैं, वे भी उस भावना को समझते हैं जो 'बहु-संबद्धता' में निहित है। यह दुनिया की हकीकतों से मुंह मोड़ना नहीं, जैसा कि 'गुटनिरपेक्षता' में था, बल्कि यह दुनिया से और भी ज़्यादा जुड़ाव है। अब जबकि भारत अपनी आज़ादी के 80वें साल में प्रवेश कर रहा है, उसे यह बात समझ आ गई कि एक क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर, जिसे अपनी परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करना है, उसके लिए बहु-संबंध बनाना ही सबसे उपयुक्त रास्ता है। ऐसा नहीं कि भारत ने अपनी बात खुलकर नहीं कही, तब भी जब पूर्व सोवियत संघ के साथ उसके संबंध गठबंधन जैसे थे। जब 1958 में बोरिस पेस्टरनाक को उनकी किताब 'डॉक्टर ज़िवैगो' के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, तो जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने लेखक को स्वीडन जाकर मेडल लेने की अनुमति दिलवाने में अगुवाई की थी। (हालांकि सोवियत संघ ने उनकी भी नहीं सुनी)। ऐसे और भी कई उदाहरण याद आते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा मुस्कुरा कर जवाब देने से लेकर - जो उन्होंने एक अमेरिकी पत्रकार को दिया था जब उसने पूछा कि भारत 'वामपंथी' है या 'दक्षिणपंथी' -जिस पर उन्होंने कहाः'हम तो सीधे खड़े हैं' - अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2000 में बिल क्लिंटन को भारत आने का निमंत्रण देने तक, जबकि दो साल पहले ही अमेरिका ने भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण उस पर प्रतिबंध लगा रखे थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत में पांच शानदार दिन बिताए; वे जहां भी गए, उनका ज़ोरदार स्वागत हुआ (जबकि पाकिस्तान में उन्होंने कड़े सुरक्षा घेरे में महज़ पांच घंटे बिताए)। उन्होंने भारत में इतना आनंद लिया कि फिर इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि किसने किसे सज़ा दी थी और किसने किसको माफ़ किया। यही कारण है कि 'कोट-टेल स्कूल ऑफ़ डिप्लोमेसी' (किसी शक्तिशाली देश की छत्रछाया में रहकर लाभ उठाने की कूटनीति)-जैसा जापान और आसियान देश बीते कई दशक से कर रहे हैं-भारत के संदर्भ में कारगर नहीं हो सकते। यह देश इतना विशाल, अलग, विविध व जटिल है कि इसे किसी एक तय ढांचे में फ़िट नहीं किया जा सकता। यही वजह कि उत्तर प्रदेश में लागू की गई 'एक ज़िला, एक व्यंजन' नीति-जिसमें एक भी व्यंजन मांसाहारी नहीं-बाकी जगह असफल होना तय है। अपनी भोजन नीति को कुछ विस्तार देते हुए,भाजपा ने यह बात समझ ली है कि जिन उत्तर भारतीय राज्यों में उसकी सरकारें हैं, वहां लागू किए गए 'गोमांस प्रतिबंधों' को वह पूर्वोत्तर भारत में अपने सहयोगी दलों पर थोप नहीं सकती। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का अपने मूल भू-राजनीतिक केंद्र की ओर लौटना स्वागत योग्य कदम है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि इस भटकाव के कारण कुछ मुल्कों से दरारें और गहरी हो गईं, कुछ के साथ रिश्तों में खिंचाव आया, और कुछ संबंध तो पूरी तरह टूट गए। यह भी उतना ही सच है कि इस भटकाव ने हमें एक कीमती सबक सिखाया हैः 'भरोसा करो, लेकिन सत्यापना जरूरी है'। राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेता दत्तात्रेय होसाबले ने प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य करने की जो अपील की है - यह कहकर कि अपनी सीमाएं स्थिर रखें और चौकस रहें - यह नीति 'भरोसा करो, लेकिन सत्यापना जरूरी है' सिद्धांत का एक जरूरी हिस्सा है, जो सर्वकालिक महागुरु चाणक्य ने पहली बार दिया था (वाजपेयी और मनमोहन सिंह की तरह, 1980 के दशक की शुरुआत में देंग शियाओपिंग की विदेश नीति का पहला काम सीमाओं को स्थिर करना ही था; इन भद्रपुरुषों ने यह बात अच्छी तरह समझ ली थी कि शांत आस-पड़ोस देश में अंदरूनी शांति रखने का सूत्र है)। ब्रिक्स और क्वाड, दोनों का फिर से सक्रिय होना अच्छा संकेत है, क्योंकि ये दोनों ही स्थिरता के केंद्र हैं। बांग्लादेश में एक राजनीतिक खिलाड़ी को भेजना, इसी सोच का विस्तार है। सोनिया गांधी के मायके, इटली के साथ रिश्तों को और मधुर बनाना,महान इतालवी दार्शनिक मैक्यावली की सोच के अनुरूप एक छोटा सा संकेत था। अब, अपनी अंदरूनी व्यवस्था दुरुस्त करने के कठिन काम को पुनः शुरू करना होगा। सिबी जॉर्ज को केरल की यात्रा पर भेजा जाये- जिसका सारा खर्च सरकार उठाए- ताकि वे पुनः यह समझ सकें कि कैसे सीरियन ईसाई, मोपला मुसलमान और मालाबार के हिंदू नायर जैसे अलग-अलग समुदाय, एक ही कहानी समान नज़रिए से देखते हैं, इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत साबित हो सकती है।

प्रेरणा

जब तर्क ने तोड़ी छुआछूत की दीवार

लाहौर का संतराम गवर्नमेंट कॉलेज उस समय शिक्षा और जागरूकता का प्रमुख केंद्र माना जाता था। दूर-दूर से विद्यार्थी वहां पढ़ने आते थे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था और नई पीढ़ी आधुनिक विचारों की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन समाज के भीतर सदियों पुरानी कुरीतियां अब भी गहरी जड़ें जमाए बैठी थीं। जाति-पांति, ऊंच-नीच और छुआछूत जैसी संकीर्ण धारणाएं लोगों के मन में इतनी गहराई से समाई हुई थीं कि शिक्षित युवक भी उनसे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहे थे। ऐसे वातावरण में संतराम नाम का एक छात्र अपने तार्किक विचारों और निर्भीक स्वभाव के कारण विशेष पहचान रखता था। वह मानता था कि मनुष्य की असली पहचान उसके कर्म और विचारों से होती है, न कि उसके जन्म या जाति से। संतराम का स्वभाव शांत था, लेकिन सामाजिक बुराइयों के प्रति उसके भीतर गहरा विरोध था। वह किसी से कटु भाषा में बहस नहीं करता था, बल्कि उदाहरण और तर्क के माध्यम से लोगों को समझाने में विश्वास रखता था। कॉलेज के छात्रावास में रहने वाले कई छात्र उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, जबकि कुछ लोग उसके विचारों को समाज विरोधी मानते थे। उन्हीं छात्रों में एक युवक ऐसा भी था, जो छुआछूत की भावना से अत्यधिक ग्रसित था। वह स्वयं को ऊंची जाति का मानकर दूसरों से दूरी बनाकर रखता था। भोजन करते समय विशेष सावधानी बरतता था कि कोई उसे छू न दे। यदि किसी का हल्का स्पर्श भी हो जाता, तो वह भोजन छोड़ देता और उसे अपवित्र मानता। संतराम कई दिनों से उसकी इस मानसिकता को देख रहे थे। उन्हें लगता था कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मानवता और विवेक का विकास करना है। वे समझ चुके थे कि यदि इस छात्र की सोच नहीं बदली गई, तो उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। एक दिन उन्होंने उसे समझाने का निश्चय किया। दोपहर का समय था। कॉलेज के भोजन कक्ष में छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। सभी छात्र अपनी-अपनी थालियों में भोजन कर रहे थे। वातावरण सामान्य था। कोई पढ़ाई की चर्चा कर रहा था, तो कोई घर की बातें। उसी दौरान संतराम भी भोजन करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि वही छात्र एक कोने में बैठकर भोजन कर रहा है। संतराम उसकी बगल में जाकर बैठ गए। कुछ देर तक वे सामान्य रूप से भोजन करते रहे। फिर अचानक वे जान-बूझकर हल्के से उस छात्र से छू गए। जैसे ही स्पर्श हुआ, छात्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी थाली दूर खिसका दी और तेज आवाज में बोला, "संतू मुझसे छू गया है। अब मेरा भोजन अपवित्र हो गया। इस थाली का खर्च इसके नाम लिख दो।" उसकी आवाज सुनते ही भोजन कक्ष में बैठे कई छात्र उधर देखने लगे। कुछ को यह दृश्य मनोरंजक लग रहा था, जबकि कुछ लोग चुपचाप स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन संतराम के चेहरे पर तनिक भी उत्तेजना नहीं थी। उन्होंने शांत भाव से उस छात्र की बांह पकड़ ली और बोले, "जरा बैठो, पहले एक बात का उत्तर दो।" छात्र पहले तो झिझका, लेकिन सबकी नजरें अपनी ओर देखकर बैठ गया। संतराम ने कहा, "अपनी यह क्रिस्टल टोपी उतारो।" छात्र ने टोपी उतार दी। संतराम ने उसे उल्टा रखने को कहा। फिर उन्होंने पूछा, "बताओ, इसके भीतर लगी पट्टी किस चीज की बनी है?" छात्र ने सहजता से उत्तर दिया, "खाल की।" संतराम मुस्कुराए और बोले, "तो क्या मैं इस मरी हुई खाल से भी अधिक अछूत हूं? जिस खाल को तुम अपने सिर पर सम्मान के साथ लगाए घूमते हो, उससे तुम्हें कोई घृणा नहीं होती, लेकिन एक जीवित मनुष्य का स्पर्श तुम्हें अपवित्र लगने लगता है। क्या यह तुम्हें उचित लगता है?" यह सुनते ही छात्र निरुत्तर हो गया। उसके चेहरे का क्रोध धीरे-धीरे शर्म में बदलने लगा। भोजन कक्ष में बैठे अन्य छात्र भी अब पूरी गंभीरता से संतराम की बात सुन रहे थे। संतराम ने आगे कहा, "भोजन की शुद्धता किसी व्यक्ति के छूने या न छूने से नहीं होती। भोजन की वास्तविक पवित्रता उसके सात्विक और शुद्ध होने में होती है। यदि भोजन अच्छा है, तो वह मनुष्य के विचारों को भी अच्छा बनाएगा। लेकिन यदि मन के भीतर घृणा, अहंकार और भेदभाव भरा हो, तो सबसे शुद्ध भोजन भी मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं बना सकता।" उनकी आवाज में कठोरता नहीं थी, बल्कि सत्य और करुणा का भाव था। वे उस छात्र को अपमानित नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसकी सोच बदलना चाहते थे। छात्र कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से ऐसी परंपराओं को ढो रहा है, जिनका कोई तार्किक आधार नहीं है। उसने धीरे-धीरे अपनी थाली वापस खींची और फिर से भोजन करने लगा। भोजन कक्ष में बैठे छात्रों के लिए यह केवल एक साधारण घटना नहीं थी। यह उनके लिए सोचने का विषय बन गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि समाज में फैली कई मान्यताएं केवल अंधविश्वास पर आधारित हैं। यदि मनुष्य तर्क और विवेक से काम ले, तो वह आसानी से सही और गलत का अंतर समझ सकता है। उस दिन के बाद उस छात्र का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जो युवक पहले दूसरों को अपने से नीचा समझता था, अब सभी के साथ समान व्यवहार करने लगा। धीरे-धीरे उसके भीतर का अहंकार समाप्त होने लगा। संतराम और उसके बीच गहरी मित्रता हो गई। उसने समझ लिया कि सच्ची महानता जाति या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि विचारों की विशालता में होती है। यह घटना समाज के लिए एक गहरा संदेश देती है। छुआछूत जैसी कुरीतियां मनुष्य को मनुष्य से अलग करती हैं। वे समाज में घृणा और अन्याय को जन्म देती हैं। जब तक मनुष्य दूसरों को अपने समान नहीं समझेगा, तब तक वास्तविक समानता स्थापित नहीं हो सकती। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि मनुष्य को संवेदनशील और विवेकशील बनाना भी है। संतराम जैसे लोग समाज के वास्तविक सुधारक होते हैं। वे तलवार या हिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि तर्क, प्रेम और जागरूकता के द्वारा परिवर्तन लाते हैं। वे यह समझते हैं कि किसी भी सामाजिक बुराई को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका लोगों के मन को बदलना है। यदि मनुष्य स्वयं सोचने लगे और सत्य को स्वीकार करने लगे, तो समाज की अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आज भी दुनिया में कई प्रकार के भेदभाव मौजूद हैं। कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं आर्थिक स्थिति को लेकर लोग एक-दूसरे को छोटा समझते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि मानवता हमेशा उन्हीं लोगों के कारण आगे बढ़ी है, जिन्होंने समानता और प्रेम का मार्ग अपनाया। मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके विचारों और व्यवहार से होती है, न कि उसके जन्म से। यही संदेश संतराम की उस छोटी-सी घटना में छिपा हुआ था, जिसने एक युवक की सोच बदलकर उसे मानवता का वास्तविक अर्थ समझा दिया।

देश व समाज हित में डीजल व पेट्रोल की बचत के साथ-साथ स्थाई सादगी समय की मांग!

अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते जिस समय पूरे विश्व के सामने ऊर्जा संकट व महंगाई सुरसा राक्षसी की तरह मूंह खोलकर के देश की दौलत को निगलने के लिए खड़ी है, उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डीजल व पेट्रोल को बचाने व सोना ना खरीदने की सभी देशवासियों से अपील की है, क्योंकि मोदी की इस अपील पर अमल करने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला बोझ कम से कम कुछ तो कम होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर होने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद से ही देश के विभिन्न हिस्सों में मोदी के द्वारा चलाई जा रही इस राष्ट्रहित की मुहिम में शामिल होने की होड़ लग गई है। हालांकि अभी तो अधिकतर लोग सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस मुहिम में ज्यादा जुड़ रहे हैं, लेकिन सांकेतिक ही सही एक बहुत अच्छी पहल में कम से कम लोगों के जुड़ने की शुरुआत तो हुई और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इस पहल पर बड़े पैमाने पर आम लोग भी अमल करेंगे। वैसे तो देशभर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही यह मुहिम धरातल पर धीरे-धीरे रंग लाती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के आम कार्यकर्ताओं तक ने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर इस मुहिम में शामिल होकर के इसको एक आंदोलन का रूप देने का कार्य किया। जिसके बाद से ही देश भर में ज्यूडिशियरी, शीर्ष नौकरशाह, कर्मचारी व आम जनमानस तक भी मोदी की इस मुहिम में अब बड़े पैमाने पर शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। शासन-प्रशासन के शीर्ष स्तर पर काबिज बैठे हुए ताकतवर लोगों में देश भर में वाहनों के लंबे-चौड़े काफिले का त्याग करने की फिलहाल तो एक होड़ लगी हुई है। हालांकि उन लोगों का यह कदम वास्तव में दिल से खर्चों में कटौती करते हुए जीवन में सादगी अपनाने की धरातल पर एक स्थाई पहल है या सिर्फ मीडिया व सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपनी कुछ पोस्ट डालकर के वाहवाही लूटने की एक नौटंकी मात्र है, यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम युद्ध के माहौल के चलते जब पूरी दुनिया ऊर्जा व आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस अपील पर भारत में धरातल पर अमल शुरू होना देश व समाज हित के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन विचारणीय तथ्य यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह मुहिम कुछ समय की ना होकर के देश व समाज हित में धरातल पर दीर्घकालीन स्थाई रूप ले पायेगी, हालांकि यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह से युद्धों के चलते बेहद ही तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, उस माहौल का स्पष्ट रूप से संदेश है कि अब वह दौर आ गया है जब देश व समाज के हित में जनता के टैक्स के पैसे के दम पर राजा-महाराजाओं की तरह पूरी शानो-शौकत व ठाट-बाट से जीवन व्यतीत कर रहे शासन-प्रशासन के लोग सादगी से जीवनयापन करने की आम जनमानस के सामने नज़ीर पेश करते हुए लोगों को भी "सादा जीवन उच्च विचार" के लिए प्रेरित करें। वैसे भी देखा जाए तो अब देश व दुनिया में वह दौर शुरू हो गया है, जब देश व समाज के हित की बातें सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफ्तरों में बैठकर के आम जनमानस पर अपने विचार या नियम-कानून बना कर के थोप देने मात्र से ही पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि उस पर अमल करवाने के लिए शासन-प्रशासन में बैठे हुए ताकतवर लोगों को भी स्वयं अनुशासित होकर के जीवन पथ पर सादगी व जवाबदेही को अपनाकर उदाहरण पेश करना चाहिए, तब ही आम जनमानस भी उन लोगों की देखा-देखी उस पर अमल करने का कार्य करेगा। लेकिन आज के वीवीआईपी बनकर के दिखाने वाले दौर में जिस तरह के राजसी ठाट-बाट के साथ कुछ राजनेताओं व शासन-प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग सरकारी व निजी दौरों के दौरान अनाप-शनाप खर्चा करते हैं, क्या ऐसे लोग के द्वारा देश व समाज हित में उन सभी अनावश्यक खर्चों में स्वयं ही कटौती करने की पहल करके जनता के सामने एक बड़ी मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए। विचारणीय तथ्य यह भी है कि आजकल देश में जिस तरह से सरकारी या गैरसरकारी लोगों के मन में अपने आपको एक बड़ा वीवीआईपी दिखाने की चाह रहती है, वह चाहते देश व समाज हित में ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों को वीवीआईपी दिखाने की चाहत में सिस्टम का बड़ा तामझाम, लग्जरी महंगी गाड़ियों के लंबे-चौड़े काफिले, चार्टर प्लेन आदि दिखावे पर जनता के द्वारा देश के विकास के लिए दिये गये टैक्स की काफी धनराशि का दुरुपयोग होता है, जिसको तत्काल रोका जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों के द्वारा अपना भौकाल बनाने के लिए व दिखावे के लिए ली गयी अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव में होने वाले अतिरिक्त खर्चों को भी अब बिल्कुल सीमित करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से चंद लोग सिस्टम में बैठे कुछ ताकतवर लोगों की कृपा से सरकारी अमले की आड़ में जनता के टैक्स के पैसों पर मौज मस्ती करते हुए जनता का ही आये दिन उत्पीड़न करते हैं, यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों से सांठ-गांठ करके हमारे प्यारे देश में धनपशु, दलाल व अपराधी तक भी सरकारी सुरक्षा व सुविधाओं के भौकाल का आनंद लें रहे हैं, जो नियम कायदे व कानून पसंद देशभक्त देशवासियों के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। देश व समाज हित में जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दी गई धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं, महिलाओं, किसानों और उधोग-धंधों आदि के साथ-साथ देश के सर्वांगीण विकास पर खर्च हो। देश की जनता के टैक्स का धन देश के विकास और आम जनमानस की भलाई में लगे, न कि वीवीआईपी बनने की चाहत के बेफिजूल के खर्चों और शानो-शौकत में लगे। इसलिए अब देश व समाज हित में वह समय आ गया है जब शासन व प्रशासन में बैठे लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोना ना खरीदने व डीजल और पेट्रोल बचाने की पहल को दो कदम आगे बढ़ाते हुए स्वयं ही अनुशासित होकर के जीवन पथ पर सरलता व सादगी अपनाकर देश व समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करेंगें और भारत का नव निर्माण करते हुए देश को विश्व गुरु बनायेंगे।

अभियान

मां गंगा की आराधना में समर्पण, मोक्ष और सनातन संस्कृति का अलौकिक उत्सव

भारतीय सभ्यता का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह आस्था, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना का भी इतिहास है। इस भूमि पर नदियों को केवल जल का स्रोत नहीं माना गया, बल्कि उन्हें जीवनदायिनी मां के रूप में पूजा गया। इन्हीं पवित्र नदियों में मां गंगा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। हिमालय की गोद से निकलकर करोड़ों लोगों के जीवन को सींचने वाली गंगा भारत की आत्मा कही जाती है। भारतीय संस्कृति, भक्ति और लोकजीवन में गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि श्रद्धा, मोक्ष और करुणा की जीवंत धारा है। यही कारण है कि गंगा दशहरा का पर्व भारतीय समाज में अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है।

गंगा दशहरा वह पावन अवसर है, जब मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में भक्तजन उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं और अपने पवित्र जल से मानव जीवन को शुद्धता, मुक्ति और नई चेतना प्रदान की थी। इस वर्ष यह पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। तिथि 25 मई को प्रातः 4:30 बजे से आरंभ होकर 26 मई को प्रातः 5:10 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के कारण पर्व 25 मई को ही मान्य होगा। विशेष बात यह है कि इस बार गंगा दशहरा सोमवार को पड़ रहा है, जो भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे इस पर्व की आध्यात्मिक महत्ता और अधिक बढ़ गई है।

गंगा अवतरण की कथा भारतीय पुराणों में अत्यंत श्रद्धा के साथ वर्णित है। कहा जाता है कि राजा सगर के साठ हजार पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही थीं। तब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने तप, संयम और समर्पण का मार्ग अपनाया। उनकी भक्ति और लोककल्याण की भावना से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हुईं। किंतु उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर उनके वेग को नियंत्रित किया और धीरे-धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही दिव्य घटना गंगा अवतरण कहलाती है।

यह कथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। भगीरथ का तप यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं होती, बल्कि लोककल्याण के लिए भी होती है। वहीं भगवान शिव का गंगा को अपनी जटाओं में धारण करना यह दर्शाता है कि शक्ति और करुणा का संतुलन ही संसार को सुरक्षित रख सकता है। इसी कारण भारतीय समाज में किसी महान और कठिन प्रयास को आज भी "भगीरथ प्रयत्न" कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन देशभर के गंगा घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, ऋषिकेश और गंगासागर जैसे तीर्थस्थलों पर लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। सुबह होते ही घाटों पर मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और "हर-हर गंगे" के जयकारे गूंजने लगते हैं। भक्त मां गंगा के जल में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और आत्मिक शांति की कामना करते हैं। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से मनुष्य के दस प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। 'दश' अर्थात दस और 'हरा' अर्थात नाश करने वाली। इसी कारण इस पर्व को गंगा दशहरा कहा जाता है।

संध्या के समय गंगा आरती का दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है। जब हजारों दीप गंगा की लहरों पर तैरते हैं और भक्त भक्ति गीतों के साथ मां गंगा की स्तुति करते हैं, तब वातावरण पूरी तरह दिव्यता से भर उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। इस समय श्रद्धालु अपने जीवन की परेशानियों, दुखों और इच्छाओं को मां गंगा के चरणों में समर्पित कर मानसिक शांति का अनुभव करते हैं।

गंगा दशहरा का संबंध भगवान शिव से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। चूंकि मां गंगा उनकी जटाओं से होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं, इसलिए इस दिन शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। भक्त गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की कामना करते हैं। सनातन परंपरा में गंगा जल को अमृत के समान पवित्र माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में इसका प्रयोग होता है। पूजा, विवाह, यज्ञ और अंतिम संस्कार तक में गंगा जल को शुद्धता और शुभता का प्रतीक समझा जाता है।

भारतीय भक्ति साहित्य में भी मां गंगा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास और अनेक संतों ने अपने पदों और रचनाओं में गंगा की महिमा का गुणगान किया है। तुलसीदास ने गंगा को मोक्षदायिनी कहा, जबकि कबीर ने गंगा को आत्मा की निर्मलता का प्रतीक माना। गांवों में आज भी लोग गंगा जल हाथ में लेकर सत्य बोलने की शपथ लेते हैं। यह विश्वास केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि नैतिक चेतना और सत्य के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है।

गंगा दशहरा के अवसर पर देशभर में मेले और धार्मिक आयोजन होते हैं। गंगा तटों पर भजन-कीर्तन, कथा-प्रवचन, भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्रद्धालु दूर-दूर से इन आयोजनों में भाग लेने आते हैं। लोकगीतों और भक्ति संगीत से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। यह पर्व केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारतीय लोकसंस्कृति और सामाजिक एकता का भी उत्सव बन जाता है। आधुनिक समय में गंगा दशहरा का महत्व पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में और भी अधिक बढ़ गया है। जिस गंगा को हम मां कहकर पूजते हैं, वही आज प्रदूषण, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे जैसी समस्याओं से जूझ रही है। बढ़ती जनसंख्या और आधुनिक विकास ने गंगा की निर्मलता को प्रभावित किया है। अनेक स्थानों पर गंगा का जल प्रदूषित हो चुका है, जो चिंता का विषय है।

ऐसे समय में गंगा दशहरा हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और आरती तक सीमित नहीं होती। यदि हम वास्तव में मां गंगा का सम्मान करते हैं, तो हमें उनकी स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने का संकल्प भी लेना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में अनेक स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संस्थाएं गंगा तटों की सफाई के लिए अभियान चला रही हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर हजारों लोग गंगा सफाई अभियान में भाग लेकर यह संकल्प लेते हैं कि वे नदी को प्रदूषित नहीं होने देंगे। यह पहल बताती है कि धर्म और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं।

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में गंगा दशहरा जैसे पर्व मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करते हैं। आधुनिक मनुष्य भौतिक सुखों की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि वह प्रकृति और आत्मिक चेतना से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल धन और उपलब्धियों का नाम नहीं है। मन की शांति, करुणा, सेवा और प्रकृति के प्रति सम्मान भी उतने ही आवश्यक हैं।

मां गंगा की धारा हमें निरंतर बहते रहने और सबको समान रूप से अपनाने की प्रेरणा देती है। वह किसी से भेदभाव नहीं करती। अमीर-गरीब, ऊंच-नीच, जाति और धर्म से ऊपर उठकर वह सभी को समान रूप से जीवन प्रदान करती है। यही भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा संदेश है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।

गंगा भारतीय सभ्यता की जीवनरेखा है। उसकी धारा केवल खेतों को नहीं सींचती, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति को भी जीवित रखती है। हिमालय से निकलकर समुद्र तक पहुंचने वाली गंगा भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसकी गोद में अनेक नगर बसे, अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं और असंख्य संतों-महात्माओं ने आध्यात्मिक चेतना का संदेश दिया।

गंगा दशहरा का वास्तविक संदेश यही है कि मनुष्य अपने भीतर पवित्रता, प्रेम और सेवा की भावना विकसित करे। जिस प्रकार मां गंगा बिना किसी भेदभाव के सबको जीवन देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रेम, करुणा और लोककल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। यही इस पर्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा है और यही भारतीय संस्कृति की अमर पहचान भी।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

पद्म पुरस्कारों की घोषणाः गुजरात के 5 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जो तीन श्रेणियों में दिए जाते हैंः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, जनसंपर्क, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण सर्वोच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस दौरान गुजरात के 5 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके विवरण इस प्रकार हैंः

श्री रतिलाल मोहनलाल बोरिसागर एक प्रसिद्ध गुजराती लेखक हैं जो अपने हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक लेखन के लिए जाने जाते हैं।

श्री बोरिसागर का जन्म 31 अगस्त , 1938 को गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनकी शैक्षणिक योग्यताएं एम.ए. (MA), बी.एड. (B.Ed.) और पी.एच.डी. (Ph.D.) हैं । एक शिक्षक के रूप में, उन्होंने 1957 से 1974 तक प्राथमिक , माध्यमिक और महाविद्यालय स्तरों पर अध्यापन कार्य किया । इसके बाद, उन्होंने 1974 में गुजरात राज्य विद्यालय पाठ्यपुस्तक बोर्ड , गांधीनगर में शिक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। वे 1998 में इसी संस्था से उप निदेशक (शिक्षा) के पद से सेवानिवृत्त हुए ।

श्री बोरिसागर ने 1955 के आसपास लिखना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में छोटी कहानियाँ लिखीं , लेकिन बाद में उन्होंने हल्की शैली में निबंध लिखना शुरू कर दिया। अपनी पहली पुस्तक 'मरक मारक' (1977) के प्रकाशन के बाद उन्होंने हल्की-फुल्की शैली में ही लिखना जारी रखा। उनकी हल्की शैली की पुस्तकें हैंः 'मरक मारक' (1977); ' आनंद लोक' (1983); ' संभवामि युगे युगे' (1994); ' एन्जॉयोग्राफी' (1997); ' तिलक कद्दी त्रिसथ हुआ' (2002); ' जीएसटी-के' (2004); ' भज आनंदम' (2007); ' अमथुन अमथुन केम ना हंसी' (2008); ' ओम हक्कयम' (2010); ' भद्रंभद्र अमर चे' (2014); ' मोज-मान रहा रे' (2017); ' विनोद-ना वैकुंठ-मान' (2017); ' त्रिन पदैया अमेरिका-मान' (2019); ' एक नहीं लेवेयेलो इंटरव्यू' (2022)। उन्होंने संस्मरणों की एक पुस्तक 'क्यां चे मारी नदी' (2021) भी लिखी है । उन्होंने ग्यारह संकलन पुस्तकें प्रकाशित की हैं (1998-2021)। उन्होंने भाषा के लिहाज से बकोर पटेल की पुरानी हास्य कहानियों की 33 पुस्तकों का संपादन किया है (2012-2013)। हरिप्रसाद व्यास द्वारा लिखित बकोर पटेल की कहानियाँ सत्तर वर्ष पहले प्रकाशित हुई थीं , इसलिए उन्हें आज के युवा पाठकों के लिए पठनीय बनाने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार का कार्य गुजराती भाषा में अपनी तरह का पहला कार्य है। उन्होंने बच्चों के लिए दो पुस्तकें प्रकाशित की हैंः 'महाभारत-ना-प्रसंग' (2002); ' श्रेष्ठ बाल खुमसिन' (2007)। उन्होंने बाल विकास पर 'बाल वंदना' (1994) नामक पुस्तक प्रकाशित की है । उन्होंने ' रमनभाई नीलकंठ' (2017) नामक जीवनी पुस्तक और 'गुजराती प्रतिकावियो' (2003) नामक आलोचना पुस्तक भी लिखी है । उन्होंने गुजराती मासिक पत्रिका 'अखंड आनंद' (1999-2005) के संयुक्त संपादक के रूप में कार्य किया है ।

शिक्षा के क्षेत्र में श्री बोरिसागर का योगदान भी उल्लेखनीय है। उन्होंने 1957 से 1974 तक सोलह वर्षों तक सावरकुंडला (अमरेली-गुजरात) में प्राथमिक , माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रदान की । उन्होंने 1974 में सावरकुंडला छोड़ दिया । 36 वर्षों के बाद , उनके प्राथमिक , माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों ने 2011 में सावरकुंडला में साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक संस्था की स्थापना की । वर्ष 2015 में , इस संस्था ने सावरकुंडला में 'श्री लल्लूभाई सेठ आरोग्य मंदिर' अस्पताल की स्थापना की। यह एक अनूठा अस्पताल है। यह पूरी तरह से निःशुल्क अस्पताल है। यहां ऑपरेशन और दवाओं सहित सभी प्रकार के उपचार के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आजकल श्री बोरिसागर अहमदाबाद स्थित 'गुजरात विश्वकोष' संस्थान में मातृभाषा - गुजराती के सही उपयोग का शिक्षण देते हैं। वे छात्रों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को लघु कथाओं और कविताओं की व्याख्या और आलोचनात्मक मूल्यांकन में भी सहायता करते हैं।

श्री बोरिसागर को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे 'मारक मारक' के लिए ज्योतिंद्र दवे कॉमेडी पुरस्कार (1976-1977) (गुजराती साहित्य परिषद) ; 'मारक मारक' के लिए द्वितीय पुरस्कार , 1977; 'आनंद लोक' के लिए प्रथम पुरस्कार , 1983; गुजरात साहित्य अकादमी , गांधीनगर , गुजरात द्वारा 'एंजियोग्राफी' के लिए प्रथम पुरस्कार , 1997। ' एंजियोग्राफी' के लिए घनश्यामदास सराफ सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार (मारवाड़ी सम्मेलन , मुंबई (1997); धनजी कांजी गांधी स्वर्ण पदक - 2002 (गुजरात साहित्य सभा) ; 2002 में गुजरात साहित्य अकादमी , गांधीनगर , गुजरात द्वारा 'तिलक काधे त्रिसाथ हो' के लिए प्रथम पुरस्कार और 2004 में 'जीएसटी-के' के लिए प्रथम पुरस्कार ; कवि दलपतराम हक्की साहित्य रत्न स्वर्ण पदक - 2011 ; सच्चिदानंद सम्मान – 2011 (गुजराती साहित्य परिषद) ;

श्री मीर हाजी कसम , जिन्हें आमतौर पर 'हाजी रामकडू' के नाम से जाना जाता है , गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक महान लोक संगीतकार हैं , जो गुजराती पारंपरिक संगीत के प्रति अपने आजीवन समर्पण और ढोलक वादन में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। छह दशकों से अधिक के कलात्मक सफर में , वे भारत की लोक विरासत के सबसे सम्मानित संरक्षकों में से एक बनकर उभरे हैं। भारत और विदेशों में उनके प्रदर्शनों ने क्षेत्रीय संगीत परंपराओं को जीवित रखने , प्रासंगिक बनाने और नई पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

27 जनवरी 1951 को जन्मे श्री कसम ने महज दस साल की उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रखा। औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद , उनकी जन्मजात प्रतिभा और समर्पण ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लोक कलाकार बना दिया। वर्षों से उन्होंने कलाकारों की कई पीढ़ियों , गुजराती फिल्म उद्योग की हस्तियों और रेडियो मंचों के साथ मिलकर लोक संगीत की धुनें जनमानस तक पहुंचाई हैं। उनकी अनूठी शैली—जिसमें वे अपने वाद्य यंत्र के साथ एकरूप हो जाते हैं—ने उन्हें स्नेहपूर्वक " रमाकाडू " उपनाम दिलाया है ।

श्री कसम ने अमेरिका , ब्रिटेन , दक्षिण अफ्रीका , कनाडा , संयुक्त अरब अमीरात , ओमान और कई अन्य देशों में प्रदर्शन करके गुजराती लोक संगीत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हजारों मंच प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया है। युवा संगीतकारों को उनका मार्गदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है—जिनमें से कई अब पेशेवर कलाकार हैं—जिसने लोक संगीत की मौखिक परंपराओं को संस्थागत रूप दिया है। वे अपने मानवीय समर्पण के लिए पूजनीय हैं। उन्होंने गौशालाओं के लिए 35,000 से अधिक परोपकारी कार्यक्रम किए हैं और जूनागढ़ में वंचित परिवारों के विवाहों में सहायता सहित सामाजिक कार्यों के लिए संगीत कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सत्तर वर्ष की आयु में भी वे बच्चों और उभरते कलाकारों को निःशुल्क लोक संगीत सिखाते रहते हैं , जो कला के माध्यम से निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है।

श्री कसम को गुजरात गौरव पुरस्कार , गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार , गुजरात लोक कला राष्ट्रीय पुरस्कार , मुख्यमंत्री का मानद पत्र और गुजरात सरकार और प्रमुख संस्थानों द्वारा दिए गए कई सांस्कृतिक पुरस्कारों सहित कई प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। दो दशकों से अधिक समय तक प्राप्त ये पुरस्कार आकस्मिक उपलब्धियों के बजाय निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाते हैं।

श्री नीलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला , जिन्हें भारत के 'ऑर्गन मैन' के नाम से जाना जाता है , देश में अंगदान के सबसे समर्पित और प्रभावशाली समर्थकों में से एक हैं। ' डोनेट लाइफ ' के संस्थापक के रूप में , उन्होंने गुजरात और पूरे भारत में मृत शरीर से अंगदान के प्रति जागरूकता और स्वीकृति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

19 अप्रैल , 1965 को जन्मे श्री नीलेश मंडलेवाला का इस मानवीय मिशन से जुड़ाव एक व्यक्तिगत अनुभव से शुरू हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उनके पिता गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे और उन्हें सप्ताह में दो बार डायलिसिस की आवश्यकता होती थी। अपने पिता की शारीरिक पीड़ा और भावनात्मक संघर्ष को देखकर , उन्होंने महसूस किया कि अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगों की गंभीर कमी के कारण भारत भर में हजारों परिवार हर साल इसी तरह की पीड़ा झेलते हैं। व्यक्तिगत पीड़ा को बोझ बने रहने देने के बजाय , उन्होंने इसे जीवन भर के लिए जीवन बचाने और इसी तरह के संकटों का सामना कर रहे परिवारों की सहायता करने के संकल्प में बदल दिया।

वर्ष 2005 में , जब भारत में अंगदान के प्रति जागरूकता अत्यंत सीमित थी और भ्रांतियों , अज्ञानता और भय से घिरी हुई थी , श्री नीलेश मंडलेवाला ने अंगदान जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की। उनका कार्य 2006 में मृत शरीर से गुर्दा दान को बढ़ावा देने से शुरू हुआ और धीरे-धीरे यकृत , हृदय , फेफड़े , अग्न्याशय , आंतों , हाथों , हड्डियों और अन्य ऊतकों के दान के प्रति जागरूकता तक विस्तारित हुआ। उनके समर्पण और विश्वसनीयता ने उन्हें जन स्वास्थ्य जागरूकता में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचान दिलाई , जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 2019 से 2021 तक अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए राज्य सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया ।

श्री नीलेश मंडलेवाला का दीर्घकालिक लक्ष्य है कि 2047 तक किसी भी नागरिक की जान अंगों की अनुपलब्धता के कारण न जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक भारत भर में व्यापक यात्राएं की हैं और जागरूकता फैलाई है। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों से जुड़ने के लिए रचनात्मक और भावनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने " अंगदान करले रे मानव तू ईश्वर बन जाएगा " गीत की रचना की और " काया - द मिशन ऑफ लाइफ " नामक लघु फिल्म का निर्माण किया , इन दोनों ने ही जन जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंगदान करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

श्री नीलेश मंडलेवाला ने मस्तिष्क मृत्यु के बारे में समुदाय को शिक्षित करने और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षणों में परिवारों को अंगदान के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनगिनत शोक संतप्त परिवारों को परामर्श दिया है और अंगदान को सुगम बनाने के लिए डॉक्टरों, अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम किया है। उनके प्रयासों से सूरत को "अंगदाता शहर" के रूप में मान्यता मिली है , जो भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। सामाजिक प्रतिरोध , गलत धारणाओं , रसद संबंधी चुनौतियों और बुनियादी ढांचे की सीमाओं का सामना करने के बावजूद , उन्होंने धैर्य , करुणा और असाधारण दृढ़ संकल्प के साथ अपने मिशन को जारी रखा है ।

कोविड -19 महामारी के दौरान , श्री नीलेश मंडलेवाला ने अस्पतालों में मस्तिष्क-मृत रोगियों के परिवारों को परामर्श देना जारी रखा और 200 से अधिक अंग और ऊतक दान में योगदान दिया। कुल मिलाकर , उनकी पहलों ने 1371 सफल अंग और ऊतक दान को सुगम बनाने में मदद की है , जिससे 1263 प्राप्तकर्ताओं को नया जीवन और उनके परिवारों को आशा मिली है। " वसुधैव कुटुंबकम " के दर्शन से प्रेरित होकर , उनके कार्य से संयुक्त अरब अमीरात , यूक्रेन , रूस , सूडान , यमन और बांग्लादेश सहित कई देशों के रोगियों को लाभ हुआ है ।

श्री नीलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला को गुजरात सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, " गुजरात गरिमा पुरस्कार " सहित 70 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है ।

श्री धर्मिकलाल चुनीलाल पांड्या को गुजरात की प्राचीन मानभट्ट "मान आख्यान" परंपरा के अग्रणी गुरु के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह एक अनूठी मौखिक कथावाचन कला है जिसकी जड़ें मध्यकालीन आख्यान साहित्य में हैं। शास्त्रीय संगीत के साथ महाकाव्यों के लयबद्ध वर्णन , काव्यात्मक अभिव्यक्ति और मान (अंगूठी वाली उंगलियों से बजाया जाने वाला तांबे का बर्तन) के अनूठे प्रयोग के माध्यम से, यह परंपरा सदियों से रामायण , महाभारत , भागवत और पुराणों के साथ-साथ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संप्रेषित करने का माध्यम रही है।

11 अगस्त 1932 को वडोदरा में जन्मे श्री पांड्या ने अपने पिता चुनीलाल पांड्या से यह कला विरासत में पाई और 1950 के दशक के आरंभ में प्रदर्शन करना शुरू किया। सात दशकों से अधिक समय से , उन्होंने इस लुप्त होती परंपरा को पुनर्जीवित करने और उसे बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित किया है, जब यह विलुप्त होने के कगार पर थी। उन्होंने व्यापक कार्यक्रमों और दीर्घकालिक कहानी सुनाने की श्रृंखलाओं के माध्यम से इस विरासत को गुजरात और पूरे भारत में विभिन्न दर्शकों तक पहुंचाया है, जिसमें राष्ट्रपति भवन जैसे प्रतिष्ठित स्थल भी शामिल हैं।

श्री पांड्या ने यूनाइटेड किंगडम , जिम्बाब्वे , जाम्बिया , संयुक्त राज्य अमेरिका , कनाडा , नेपाल और थाईलैंड में सांस्कृतिक यात्राओं और आध्यात्मिक व्याख्यानों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनभट्ट परंपरा का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे इस दुर्लभ कला रूप को वैश्विक दर्शकों और भारतीय प्रवासी समुदाय से परिचित कराया जा सका है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ उनके व्यापक रिकॉर्डिंग में हरिवंश पुराण (उत्तर महाभारत से) , शिव महापुराण और मध्यकालीन गुजराती कवि प्रेमानंद के सभी चालीस आख्यानों का संपूर्ण पाठ शामिल है । हाल के वर्षों में , उनके परिवार की डिजिटल प्रचार पहलों ने इस परंपरा की पहुंच को और भी बढ़ाया है।

शास्त्रीय संगीत को संरक्षित करने के अलावा , श्री पांड्या ने जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता जैसे समकालीन सामाजिक विषयों पर नए आख्यान रचे हैं। उन्होंने ' श्री मन आख्यान कला शिक्षण केंद्र ' के माध्यम से प्रशिक्षण को संस्थागत रूप दिया , जहाँ उन्होंने अपने पुत्रों प्रद्युम्न और मयंक पांड्या सहित कई छात्रों का मार्गदर्शन किया, जो आज भी इस कला का प्रदर्शन करते हैं , इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।

श्री पांड्या को उनके योगदान के लिए अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्हें 1983 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ , जिससे वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र मनभट्ट कलाकार बन गए। अन्य सम्मानों में 1980 में जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा कीर्तन केसरी पुरस्कार और मनकला कौशल प्रमाणपत्र ; 1980 के दशक में गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी से गौरव पुरस्कार और कई प्रशंसा पुरस्कार ; वडोदरा नगर निगम से सम्मान (1984); स्वामीनारायण विचार ट्रस्ट , अमृता संस्थान (मुंबई) , गुजरात लोककला केंद्र और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पुरस्कार (गुजरात सरकार , 1994-95) से पुरस्कार; गुजराती साहित्य अकादमी (अमेरिका, 1996) और संन्यास सेवाश्रम (काठमांडू , 2008) से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान शामिल हैं । और बाद में संस्कार भारती (वडोदरा , 2009), त्रिवेणी संस्थान (2012), 8वां दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव - संगीत नाटक अकादमी (दिल्ली , 2014), 19वां भारत रंग महोत्सव - राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (दिल्ली , 2017), गुजरात राज्य सरकार (2017), और शाजदा कला केंद्र ट्रस्ट (बेंगलुरु , 2017) से सम्मान और प्रशंसा मिली। .

श्री अरविंद वैद्य एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं जिन्होंने छह दशकों से अधिक समय तक विभिन्न पात्रों को निभाकर गुजराती थिएटर , हिंदी टेलीविजन और फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है ।

3 मई 1941 को जन्मे श्री वैद्य ने अपनी शिक्षा की शुरुआत 1966 में गुजरात विश्वविद्यालय के एच के आर्ट्स कॉलेज से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके की। इसके तुरंत बाद , वे उसी संस्थान में व्याख्याता के रूप में लौट आए , जहाँ उन्होंने युवा प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करते हुए 'परित्राण' और 'रायगढ़ झब जग्गे छे' जैसे यादगार गुजराती नाटकों का निर्देशन और अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) में सेवा की , जहाँ उन्होंने निर्माण सहायक के रूप में सार्थक कार्यक्रमों में योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने व्यापक रूप से प्रशंसित श्रृंखला 'भला भूषण भीड़ भरम' में शानदार अभिनय किया।

श्री वैद्य ने अपनी स्वयं की प्रोडक्शन कंपनी ' नाट्य संपदा ' की स्थापना की , जिसके माध्यम से उन्होंने पचहत्तर से अधिक पूर्ण नाटकों का निर्माण , निर्देशन और अभिनय किया। उनकी प्रत्येक रचना में समर्पण की गहरी भावना स्पष्ट रूप से झलकती थी , जिसने उन्हें इस क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाई । वर्ष 1993 में मुंबई ने उन्हें अपने कार्यक्षेत्र को और व्यापक बनाने के लिए आमंत्रित किया। बहुभाषी और हमेशा अनुकूलनशील होने के कारण , उन्होंने गुजराती , मराठी और हिंदी रंगमंच में सहजता से काम किया और भोजपुरी फिल्मों में भी कदम रखा। उन्होंने मराठी टेलीविजन धारावाहिक 'हरया नार्या' का निर्देशन किया और अपनी कला को नए क्षेत्रों में विस्तारित किया।

85 वर्ष की आयु में भी श्री वैद्य मंच और स्क्रीन पर सक्रिय हैं—उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने तीन सौ से अधिक नाटकों का निर्देशन या उनमें अभिनय किया है और 100 से अधिक टेलीविजन कार्यक्रमों में अपनी कला का योगदान दिया है। उनके कुछ किरदार आज भी दर्शकों के मन में बसे हुए हैं, जैसे 'नोखी मति ने नोखा मानवी' , ' एंटीमी अध्याय' , ' परित्राण' और 'अमे बर्फ ना पंखी' ; लोकप्रिय शो में 'साराभाई वर्सेस साराभाई' , ' बा बहू और बेबी' , ' खिचड़ी' , ' सास बिना ससुराल' , ' लेडीज स्पेशल' और 'अनुपमा' शामिल हैं ।

श्री वैद्य को गुजरात सरकार से गौरव पुरस्कार , दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सर्वभाषा नाटक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है , और वे गुजरात संगीत नाटक अकादमी से लगातार सम्मानित होते रहे हैं।

क्रूड ऑयल वायदा 479 रुपये फिसलाः सोना वायदा में 709 रुपये और चांदी वायदा में 4876 रुपये की वृद्धि

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 24785.38 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 217156.58 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 16161.30 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 241941.95 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 24785.38 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 217156.58 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2235.79 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 16161.30 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 159150 रुपये के भाव पर खूलकर, 159500 रुपये के दिन के उच्च और 158919 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 158679 रुपये के पिछले बंद के सामने 709 रुपये या 0.45 फीसदी की बढ़त के साथ 159388 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 473 रुपये या 0.37 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 127676 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 53 रुपये या 0.33 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15969 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जून वायदा 158998 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159259 रुपये और नीचे में 158416 रुपये पर पहुंचकर, 817 रुपये या 0.52 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 158950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 159043 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159280 रुपये और नीचे में 158420 रुपये पर पहुंचकर, 158235 रुपये के पिछले बंद के सामने 623 रुपये या 0.39 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 158858 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 276683 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 277245 रुपये और नीचे में 275215 रुपये पर पहुंचकर, 271846 रुपये के पिछले बंद के सामने 4876 रुपये या 1.79 फीसदी की तेजी के संग 276722 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 4546 रुपये या 1.65 फीसदी की तेजी के संग 280547 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 4525 रुपये या 1.64 फीसदी की बढ़त के साथ 280564 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 3030.20 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 4.2 रुपये या 0.31 फीसदी की तेजी के संग 1348.9 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मई वायदा 3.75 रुपये या 1.01 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 373.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 55 पैसे या 0.14 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 386.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 40 पैसे या 0.2 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 203.15 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5533.80 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा 8802 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8880 रुपये और नीचे में 8622 रुपये पर पहुंचकर, 479 रुपये या 5.22 फीसदी घटकर 8689 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा 478 रुपये या 5.21 फीसदी लुढ़ककर 8690 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सत्र के आरंभ में 275.1 रुपये के भाव पर खूलकर, 276.5 रुपये के दिन के उच्च और 267.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 277 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.8 रुपये या 0.65 फीसदी लुढ़ककर 275.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 1.8 रुपये या 0.65 फीसदी लुढ़ककर 275.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 975 रुपये के भाव पर खूलकर, 20 पैसे या 0.02 फीसदी चढ़कर 964 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 8768.16 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 7393.15 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2351.17 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 309.38 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 17.60 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 342.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4326.22 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1173.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 7.57 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9629 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 62602 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20168 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 318730 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 47512 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9900 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 25124 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 79596 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16181 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26086 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 208.9 रुपये की गिरावट के साथ 277 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 70 पैसे की नरमी के साथ 2.35 रुपये हुआ।

सोना मई 165000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 7 रुपये की बढ़त के साथ 98 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 280000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 57 रुपये की बढ़त के साथ 1349 रुपये हुआ। तांबा जून 1450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 74 पैसे के सुधार के साथ 10.8 रुपये हुआ। जस्ता जून 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 20 पैसे के सुधार के साथ 9 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 56.4 रुपये की बढ़त के साथ 338 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 85 पैसे के सुधार के साथ 8.3 रुपये हुआ।

सोना मई 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 134.5 रुपये की गिरावट के साथ 114 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 270000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2551 रुपये की गिरावट के साथ 641.5 रुपये हुआ। तांबा जून 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.68 रुपये की गिरावट के साथ 9.96 रुपये हुआ। जस्ता जून 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.22 रुपये की गिरावट के साथ 8.5 रुपये हुआ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के अनुरूप, VGRC सेंट्रल गुजरात में GI टैग उत्पाद हो सकते हैं प्रदर्शित

▶▶ सेंट्रल गुजरात की GI टैग प्राप्त हस्तशिल्प विरासत को मिलेगा वैश्विक मंच

▶▶ 'वोकल फॉर लोकल' के तहत स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक कलाओं को मिलेगा बढ़ावा

▶▶ अहमदाबाद सोदागरी ब्लॉक प्रिंट, माता नी पछेड़ी और सांखेड़ा फर्नीचर रहेंगे प्रमुख आकर्षण

▶▶ VGRC-मध्य गुजरात, पारंपरिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों और वैश्विक निवेशकों से जोड़ने का बनेगा माध्यम

गांधीनगर, 25 मई : जून के अंतिम सप्ताह में वडोदरा में आयोजित होने वाली सेंट्रल गुजरात क्षेत्र की आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) औद्योगिक विकास को गति देने के साथ-साथ क्षेत्र की समृद्ध हस्तशिल्प एवं सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगी।

VGRC-मध्य गुजरात में दिखेगी सेंट्रल गुजरात की सांस्कृतिक और हस्तशिल्प विरासत

इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल गुजरात के उन हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किए जाने की संभावना है, जिन्हें भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हो चुका है अथवा जो वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया में हैं। GI टैग किसी उत्पाद की विशिष्ट पहचान, गुणवत्ता और उसके भौगोलिक मूल से जुड़े विशेष महत्व को मान्यता प्रदान करता है। सेंट्रल गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में अहमदाबाद सोदागरी ब्लॉक प्रिंट, माता नी पछेड़ी, पिथोरा पेंटिंग, पेथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स, अगेट्स ऑफ कैम्बे तथा सांखेड़ा फर्नीचर जैसे अनेक GI टैग प्राप्त उत्पाद शामिल हैं।

सदियों पुरानी परंपराएं बन रही हैं वैश्विक पहचान

अहमदाबाद के जामालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संरक्षित हस्त-मुद्रित वस्त्र कला 'सोदागरी ब्लॉक प्रिंट' को वर्ष 2024 में GI टैग प्राप्त हुआ। पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली

आ रही इस परंपरागत कला का अभ्यास मुख्यतः छीपा समुदाय द्वारा किया जाता है। अहमदाबाद और खेड़ा जिलों की प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र कला 'माता नी पछेड़ी' को वर्ष 2023 में GI टैग मिला। देविपूजक समुदाय द्वारा संरक्षित इस कला में कपड़े पर देवी-देवताओं के चित्र उकेरे जाते हैं।

राठवा, भील और भिलाला जनजातियों द्वारा प्रचलित अनुष्ठानिक भित्ति कला 'पिथोरा पेंटिंग' अपने जीवंत रंगों, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति और विशिष्ट शैली के लिए जानी जाती है। इस कला को वर्ष 2021 में GI टैग प्राप्त हुआ तथा यह मुख्यतः छोटाउदेपुर और पंचमहल जिलों में प्रचलित है। इसी प्रकार, गांधीनगर जिले के पेथापुर गांव में पिछले लगभग 300 वर्षों से प्रचलित 'पेथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स' की हस्तकला को वर्ष 2018 में इसकी विशिष्ट हस्त-नक्काशी तकनीक के लिए GI टैग प्राप्त हुआ।

हड़प्पा सभ्यता से आधुनिक वैश्विक बाजार तक का सफर

आणंद जिले के खंभात (पूर्व में कैम्बे) में तैयार किए जाने वाले रत्न 'अगेट्स ऑफ कैम्बे' को वर्ष 2008 में GI टैग मिला। अगेट शिल्पकला का इतिहास हड़प्पा सभ्यता तक जुड़ा हुआ माना जाता है। वडोदरा जिले के सांखेड़ा कस्बे में खारड़ी-सुथार समुदाय द्वारा निर्मित आकर्षक हस्तनिर्मित 'सांखेड़ा फर्नीचर' को भी वर्ष 2008 में GI टैग प्राप्त हुआ। इस शिल्प में सागौन की लकड़ी से बने फर्नीचर को पारंपरिक रूप से मैरून और सुनहरे रंगों से सजाया जाता है। इसके अलावा, दाहोद बीड वर्क और खंभात काइट जैसे उत्पाद, जिन्होंने GI टैग के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी VGRC (सेंट्रल गुजरात) में प्रदर्शित किए जाने की संभावना है।

'वोकल फॉर लोकल' से स्थानीय कला को मिलेगा वैश्विक मंच

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 विजन के अनुरूप इन पारंपरिक उत्पादों को 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। वडोदरा में आयोजित होने वाली आगामी VGRC सेंट्रल गुजरात के GI टैग प्राप्त उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए पारंपरिक कारीगरों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व संस्करण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रभावी मंच के रूप में स्थापित हुए हैं।

निवेश, नेटवर्किंग और नवाचार का संगम बनेगी आगामी VGRC- मध्य गुजरात

इन रीजनल कॉन्फ्रेंस में एमओयू आदान-प्रदान के अतिरिक्त वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिवर्स बायर-सेलर मीट, व्यापार प्रदर्शनियां तथा सेक्टर-विशिष्ट पवेलियन आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन, MSME के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार, विशेष B2B एवं B2G नेटवर्किंग सत्र, उद्यमी मेला, औद्योगिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण तथा वैश्विक प्रवासी समुदाय के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारी समझौते भी प्रमुख आकर्षण रहते हैं।

स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक निवेशकों से जोड़ते हुए तथा क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नवाचार को प्रदर्शित करती आगामी VGRC, सेंट्रल गुजरात की संभावनाओं को विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रभावी मंच साबित होगी।

श्रम मंत्री कांतिलाल ने किया कमाल! दस लाख पेड़ लगाकर मोरबी को बनाया हरा-भरा

▸▸ कांतिलाल ने कैंसर से नहीं मानी हार, शेष जीवन प्रकृति की गोद में समर्पित करने का संकल्प किया

▸▸ 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सबसे बड़े वन कवच 'नमो वन' का लोकार्पण किया था

▸▸ हाल में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने एक बार फिर इस नमो वन का दौरा किया और 3 करोड़ रुपए के खर्च से आइकॉनिक रोड बनाने के लिए विशेष ग्रांट आवंटित की, ताकि लोग इस वन का आनंद उठा सकें

▸▸ मोरबी के विधायक हैं श्री कांतिलाल अमृतिया, 2025 में मच्छू डैम-2 के किनारे 1200 बीघा जमीन पर दस लाख पेड़ लगाकर बंजर भूमि को जंगल में बदला

गांधीनगर : बमुश्किल आठ महीने पहले तक मोरबी, जो भारत का सिरेमिक हब है, के बाहरी इलाके में मच्छू डैम-2 के किनारे श्री मोरबी पांजरापोल ट्रस्ट के स्वामित्व वाली 1200 बीघा की विशाल बंजर जमीन उपेक्षित हालत में थी। आज वही जमीन राज्य के श्रम, कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री श्री कांतिलाल अमृतिया के अथक प्रयासों से 'नमो वन' में बदल गई है। गत वर्ष सितंबर में लगाए गए दस लाख से अधिक पौधों के कारण आज इस बंजर जमीन ने हरियाली की चुनर ओढ़ ली है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गत वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर इस वन कवच (नमो वन) का लोकार्पण किया था। आठ महीने पहले जो इलाका वीरान और बंजर था, आज वहां हरियाली लहलहा रही है।

श्री कांतिलाल अमृतिया, जिन्हें लोग प्यार से 'काना भाई' कहकर बुलाते हैं, सौराष्ट्र की सबसे बड़ी मानी जाने वाली श्री मोरबी पांजरापोल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इस ट्रस्ट के पास 4500 बीघा जमीन है। पर्यावरण को बचाने और समाज के लिए एक अनुकरणीय कार्य करने की सोच के साथ कांतिलाल अमृतिया ने इस बंजर भूमि की तस्वीर बदलने का भगीरथ कार्य शुरू किया और गुजरात का सबसे बड़ा 'वन कवच' (नमो वन) बनाने का दृढ़ निश्चय किया।

उन्होंने मच्छू डैम-2 के किनारे स्थित ट्रस्ट की 1200 बीघा जमीन पर दस लाख पेड़ लगाने का बड़ा अभियान शुरू किया। इससे पहले, उन्होंने मच्छू डैम के किनारे आठ चेकडैम बनाए हैं और जल संचय करने का उत्कृष्ट कार्य किया है।

500 लोगों ने रोज 25 से 30 हजार पौधे लगाए

अभियान के शुरुआती दौर की यादों को ताजा करते हुए श्री कांतिलाल अमृतिया ने बताया, "जब हमने एक महीने में दस लाख पौधे लगाने का निर्णय किया, तब पौधरोपण के क्षेत्र में बड़ा काम करने वाली संस्था सद्भावना वृद्धाश्रम की मदद से एक विस्तृत योजना बनाई।"

श्री अमृतिया ने आगे कहा, "हमने अपने इस यज्ञ में सद्भावना वृद्धाश्रम को शामिल किया। चूंकि जमीन अनुपजाऊ और बंजर थी, इसलिए सबसे पहले उसे समतल किया। मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बाहर से हजारों टन उर्वर मिट्टी लाकर यहां लाकर डाली, साथ ही बड़ी मात्रा में गोबर खाद डालकर जमीन को उपजाऊ बनाया। 1200 बीघा जमीन के चारों ओर बाड़ लगाई। इसके बाद पौधरोपण के लिए एक साथ 500 लोगों ने साथ मिलकर रोजाना लगभग 25 से 30 हजार पौधे लगाने का भगीरथ कार्य शुरू किया। केवल 37 दिनों के अथक प्रयासों के बाद हम 10 लाख पौधे लगाने में सफल रहे।" 17 सितंबर, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर मोरबी में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने किया 'नमो वन' का लोकार्पण किया

कांतिलाल अमृतिया ने कहा कि दस लाख पौधों को नियमित रूप से खाद-पानी देने की व्यवस्था की गई है। इसका प्रबंधन सद्भावना वृद्धाश्रम करता है। आज, आठ महीने के बाद ये दस लाख पौधे अब पेड़ों में बदल गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आइकॉनिक रोड बनाने के लिए तीन करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट आवंटित की

श्री कांतिलाल अमृतिया ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भी हमारे इस काम में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी दिखाई है। हाल में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले उन्होंने दूसरी बार 'नमो वन' का दौरा किया। उन्होंने यहां एक आइकॉनिक रोड बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट आवंटित की है, ताकि लोग इस वन कवच तक पहुंच सकें और इसका आनंद उठा सकें।"**कांतिलाल ने कैंसर को हराया, अब शेष जीवन प्रकृति को समर्पित**

64 वर्षीय श्री कांतिलाल अमृतिया ने हाल ही में कैंसर का पता चलने पर सर्जरी करवाई है। एक आम इनसान कैंसर का नाम सुनते ही हिम्मत हार जाता है, लेकिन कांतिलाल उनमें से नहीं हैं। पांच कीमोथेरेपी पूरी करने के बाद अभी वे इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं। इस मुश्किल हालात में भी उनका जनसंपर्क जारी है। उन्होंने कहा कि इस कैंसर से बचाकर प्रकृति ने उन्हें दूसरा जीवन दिया है और वे इस दूसरी जिंदगी प्रकृति को ही समर्पित करना चाहते हैं।

छह बार विधायक चुने गए श्री कांतिलाल अमृतिया ने शेष जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा, "कैंसर की सर्जरी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। अब मैं अपना जीवन प्राकृतिक कृषि और वृक्षारोपण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित करना चाहता हूं। हमने सरकार को पत्र लिखकर मच्छू डैम के किनारे स्थित सरकारी जमीन आवंटित करने की मांग की है, ताकि वहां भी इस प्रकार का विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया जा सके।"

पश्चिम रेलवे द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026,अभियान के माध्यम से हरित पहल को प्रोत्साहन

मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा स्थिरता एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान, स्वच्छता गतिविधियाँ तथा पर्यावरण-अनुकूल पहलों का आयोजन

राष्ट्रव्यापी विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के अंतर्गत, जिसे 15 मई से 5 जून, 2026 तक मनाया जा रहा है, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, डिपो, ईएमयू कार शेडों, रेलवे कॉलोनियों तथा अन्य रेलवे इकाइयों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी विभिन्न पहलें की गईं। इन गतिविधियों का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, यात्रियों एवं अन्य हितधारकों के बीच स्थिरता, स्वच्छता, जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देना है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान की शुरुआत सभी मंडलों में विश्व पर्यावरण दिवस गतिविधियों के शुभारंभ के साथ हुई। साथ ही #MissionLiFE तथा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 विषयों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण शपथ भी दिलाई गई, जिसमें कर्मचारियों एवं हितधारकों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने तथा सतत भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर जलवायु परिवर्तन, सतत जीवनशैली तथा "सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें" संदेश से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं डिजिटल संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए। यात्रियों एवं रेलवे उपयोगकर्ताओं को पुनः उपयोग योग्य पानी की बोतलों, पर्यावरण-अनुकूल बैगों तथा पुनः उपयोग योग्य कंटेनरों के उपयोग जैसी हरित आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। "अपनी पानी की बोतल स्वयं साथ रखें" संदेश के माध्यम से रेलवे परिसरों में प्लास्टिक कचरे को कम करने हेतु विशेष जन-जागरूकता गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं।

मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा स्टेशनों, कोचिंग डिपो, ईएमयू कार शेडों तथा अन्य इकाइयों में प्रभावी अपशिष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाए गए। यात्रियों को पृथक कूड़ेदानों का सही उपयोग करने तथा स्वच्छ रेलवे वातावरण बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी के लिए जागरूक किया गया। स्थानीय जनसमुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ रेलवे स्टेशनों एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान भी आयोजित किए गए, जिससे स्वच्छ एवं हरित वातावरण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिला।

इसके अतिरिक्त, रेलवे कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों के लिए कार्यशालाएँ एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जलवायु कार्रवाई, उचित अपशिष्ट पृथक्करण, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक उपयोग में कमी तथा दैनिक कार्यों में सतत पर्यावरणीय व्यवहार अपनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। मंडल द्वारा प्लास्टिक रहित, पर्यावरण-अनुकूल कटलरी एवं जैव-अपघटनीय विकल्पों को भी बढ़ावा दिया गया। साथ ही RailOne एवं अन्य ऑनलाइन अनुप्रयोगों के माध्यम से डिजिटल टिकटिंग एवं पेपरलेस यात्रा को प्रोत्साहित कर कागज की खपत कम करने तथा सतत यात्रा पद्धतियों को समर्थन दिया गया।

इन पहलों के माध्यम से पश्चिम रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, स्वच्छता तथा जनभागीदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया है, जिससे स्वच्छ, हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल रेलवे प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

वायरल वीडियो मामले में अनंत सिंह को फिलहाल राहत, गिरफ्तारी पर रोक से बढ़ी राजनीतिक हलचल

गोपालगंज। हथियार लहराने और कथित अश्लील डांस के वायरल वीडियो मामले में मोकामा से जदयू विधायक Anant Singh को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। गोपालगंज की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 मई तय की है। अदालत के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है, क्योंकि मामला एक जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक मंच पर कथित हथियार प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।

इस मामले में विधायक अनंत सिंह समेत कुल नौ लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। हालांकि अदालत से फिलहाल केवल अनंत सिंह को ही अंतरिम राहत मिली है, जबकि अन्य आरोपितों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों और प्रस्तुत साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद आगे का आदेश पारित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने अदालत में विधायक का पक्ष रखा। वकीलों ने दलील दी कि वायरल वीडियो के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है और वीडियो की सत्यता तथा संदर्भ की गहन जांच अभी बाकी है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो संपादित हो सकता है और उसमें दिखाई गई घटनाओं को वास्तविकता से अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि जांच पूरी होने तक विधायक को राहत दी जाए, क्योंकि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने सुनवाई के बाद बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 जोड़ने के लिए अदालत में आवेदन दिया गया है। हालांकि अदालत ने फिलहाल उस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष का मानना है कि मामले में लगाए गए आरोपों और कानूनी धाराओं की समीक्षा आवश्यक है और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। यह पूरा मामला 3 मई को गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित एक निजी कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग कथित रूप से हथियार लहराते और मंच पर डांस करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू की गई। वीडियो के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई थी, क्योंकि कार्यक्रम में विधायक अनंत सिंह की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए गए थे।

घटना के बाद विधायक अनंत सिंह ने सफाई देते हुए कहा था कि कार्यक्रम स्थल से उनके निकलने के बाद क्या हुआ, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि वायरल वीडियो को लेकर कई तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं और मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि जांच एजेंसियां उन्हें बुलाती हैं तो वह पूरा सहयोग करेंगे। मामले में अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्षी दल इस मामले को कानून-व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से जोड़कर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि जदयू नेताओं का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

अब सबकी नजर 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जब अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई और राहत को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है। वायरल वीडियो और हथियार प्रदर्शन से जुड़ा यह मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और कानून-व्यवस्था पर बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है।

ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को राहत, फिर भी रोज 600 करोड़ का घाटा

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चार चरणों में हुई बढ़ोतरी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन वित्तीय दबाव अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। केंद्र सरकार और तेल कंपनियों के सामने बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों, रियायती एलपीजी वितरण और घरेलू बाजार में कीमतों को संतुलित रखने की चुनौती बनी हुई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव Sujata Sharma ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि कीमतों में हालिया संशोधन के बाद तेल कंपनियों का दैनिक घाटा घटकर लगभग 600 करोड़ रुपये रह गया है। उन्होंने बताया कि 15 मई से पहले स्थिति कहीं अधिक गंभीर थी। उस समय पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा था। लगातार बढ़ते घाटे के कारण तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति

पर दबाव बढ़ रहा था और बाजार में ईंधन आपूर्ति तथा मूल्य संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। सरकार और तेल कंपनियों की ओर से चार चरणों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी किए जाने के बाद घाटे में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार मूल्य संशोधन से कंपनियों को राहत मिली है, लेकिन घरेलू रसोई गैस एलपीजी पर दी जा रही सब्सिडी और रियायती दरों के कारण अब भी कंपनियों पर भारी वित्तीय बोझ बना हुआ है। सुझाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की वास्तविक लागत और उपभोक्ताओं को तय रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाने के बीच का अंतर वहन करती है। इसके बावजूद तेल कंपनियों को कुल मिलाकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया that पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद एलपीजी पर जारी राहत योजनाओं के कारण घाटा पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों का सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो आने वाले दिनों में घरेलू ईंधन कीमतों पर फिर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर सरकार महंगाई और आम जनता पर पड़ने वाले असर को देखते हुए कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश में भी जुटी हुई है।

ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देशभर में महंगाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों, रोजमर्रा की वस्तुओं और निर्माण सामग्री की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर हमला बोल रहा है और तेल कंपनियों पर मुनाफाखोरी के आरोप लगा रहा है।

हालांकि सरकार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में कीमतों को पूरी तरह स्थिर रखना आसान नहीं है, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। सरकार और तेल कंपनियां उपभोक्ताओं पर कम से कम बोझ डालते हुए वित्तीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और घरेलू मांग के आधार पर ईंधन कीमतों को लेकर आगे के फैसले लिए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई 'नागरिक देवो भव:' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में गुजरात का वन डे गवर्नेंस से व्हाट्सएप गवर्नेंस की ओर एक महत्वपूर्ण कदम

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस को गति देकर नागरिकों को व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी

▸▸ गुजरात सरकार और मेटा के बीच व्हाट्सएप आधारित सिटीजन सर्विस डिलीवरी को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू गांधीनगर में संपन्न हुआ

▸▸ लाइन से ऑनलाइन तक की सुगम डिजिटल पहल को गति देने वाला एमओयू

▸▸ ग्रामीण और शहरी नागरिकों को शिकायत निवारण सहित आय-जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, राशन कार्ड अपडेट, राजस्व रिकॉर्ड तथा आधिकारिक शपथपत्र जैसी लगभग 20 सरकारी सेवाएं एक ही व्हाट्सएप नंबर से घर बैठे मिल सकेंगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई 'नागरिक देवो भवः' की परिकल्पना को वन डे गवर्नेंस से व्हाट्सएप गवर्नेंस के माध्यम से साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में राज्य सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के बीच एक एमओयू गांधीनगर में संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में राज्य सरकार ने जीएआरसी की सिफारिशों के अनुसार 'सुगम डिजिटल गुजरात' पहल के तहत पांच प्रमुख विभागों की लगभग 20 नागरिक केंद्रित सेवाएं व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं।

अब इन सेवाओं को लोगों के लिए अधिक सरल और तेज बनाने के साथ-साथ सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सेवा वितरण सुनिश्चित करने में मेटा और राज्य सरकार के बीच हुआ यह एमओयू महत्वपूर्ण साबित होगा। तद्नुसार; अंग्रेजी और गुजराती भाषा में व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट के जरिए राज्यभर के नागरिक एक ही व्हाट्सएप नंबर से इन 20 महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ आने वाले समय में घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ही प्राप्त कर सकेंगे।

इतना ही नहीं; इन सेवाओं के लिए अलग-अलग वेब पोर्टल पर जाने या कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाकर लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता से भी आने वाले दिनों में मुक्ति मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा जो सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाएंगी, उनमें शिकायत निवारण सहायता, आय, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, राशन कार्ड अपडेट, राजस्व रिकॉर्ड तथा आधिकारिक शपथपत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। इस एमओयू के लागू होने से आने वाले समय में सेवा वितरण प्रक्रिया अधिक सरल होने के साथ-साथ रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग भी अधिक मजबूत होगी। राज्य सरकार आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से और अधिक सेवाओं को भी इस व्हाट्सएप आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़ने की मंशा रखती है।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू होने वाली इस नई व्हाट्सएप गवर्नेंस आधारित नागरिक केंद्रित सेवाओं का सबसे बड़ा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। विशेष रूप से अब सरकारी सेवाएं अधिक आसान बनेंगी, सेवाएं मोबाइल पर कुछ ही क्लिक में उपलब्ध होंगी, समय और खर्च दोनों की बचत होगी तथा पारदर्शिता और जवाबदेही और अधिक सुदृढ़ होगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकार की सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी का लाभ अब आम आदमी तक घर बैठे पहुंचेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिक केंद्रित गवर्नेंस की जो दिशा दी है, उसमें गुजरात ने वन डे गवर्नेंस जैसी पहल के माध्यम से समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने की शुरुआत कर सामान्य नागरिक को कम से कम परेशानी और अधिक से अधिक सुविधा मिले, इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में लगातार सफल प्रयास किए हैं।

शहरी क्षेत्रों में जन सेवा केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में वीसीई आधारित व्यवस्था के माध्यम से लाखों नागरिकों तक सरकार की सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही हैं। अब मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (मेटा) के साथ हुए इस एमओयू के जरिए गुजरात नागरिक केंद्रित गवर्नेंस के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है।

आने वाले समय में नागरिकों को अपने मोबाइल पर कुछ ही क्लिक में एंड टू एंड सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का मार्ग और अधिक मजबूत होगा। केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ स्वरूप में उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री की प्रेरक उपस्थिति में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव श्री हारित शुक्ला तथा मेटा के डायरेक्टर एवं हेड ऑफ पॉलिसीज श्री अमन जैन और कंट्री डायरेक्टर श्री ए. श्रीनिवास ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर कर एक-दूसरे को इसकी प्रति सौंपी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अंजु शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा सचिव डॉ. अजय कुमार भी उपस्थित रहे।

धोलेरा की रफ्तार को मिला सरकारी भरोसा, विकास कार्यों की समीक्षा में दिखा 'विकसित भारत' का विजन

धोलेरा। गुजरात का महत्वाकांक्षी औद्योगिक और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट धोलेरा अब तेजी से देश के सबसे बड़े निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रों में अपनी पहचान बना रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के उप मुख्यमंत्री Harsh Sanghavi ने शनिवार को धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR) का विस्तृत दौरा कर यहां चल रहे विकास कार्यों और औद्योगिक तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विकसित किए जा रहे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहायशी सुविधाओं और औद्योगिक परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और डेवलपर्स से प्रगति रिपोर्ट ली। दौरे को धोलेरा के विकास की दिशा में सरकार की बढ़ती प्राथमिकता और 'विकसित भारत 2047' के विजन से जोड़कर देखा जा रहा है।

धोलेरा को भविष्य के औद्योगिक और शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार लगातार बड़े स्तर पर निवेश और आधारभूत संरचना तैयार करने में जुटी हैं। उप मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार एस.एस. राठौड़, उद्योग सचिव ममता वर्मा, पर्यटन सचिव एवं डीआईसीडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप आर्य और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रुशिन भट्ट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने धोलेरा में चल रहे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल गतिविधियों और आने वाले निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी।

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एक्टिवेशन एरिया में विकसित किए जा रहे GAP ग्रुप के बहुचर्चित अखिलम टाउनशिप प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। GAP ग्रुप के चेयरमैन Gopal Goswami, मैनेजिंग डायरेक्टर Ambarish Parajiya और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि पटेल ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें संकल्प पत्र, शंख और भगवद गीता की प्रति भेंट की गई। इसे 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय संकल्प और औद्योगिक विकास में सामूहिक भागीदारी का प्रतीक बताया गया।

GAP ग्रुप के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को अखिलम टाउनशिप प्रोजेक्ट की प्रगति और उसकी विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना धोलेरा में तेजी से बढ़ती रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही है। प्रोजेक्ट में आधुनिक स्टूडियो अपार्टमेंट्स, को-वर्किंग स्पेस, फूड कोर्ट और अन्य लाइफस्टाइल सुविधाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि यहां आने वाले उद्योगों, कर्मचारियों और निवेशकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने परियोजना की प्रगति और आधुनिक सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि धोलेरा में जिस गति से औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए गुणवत्तापूर्ण रिहायशी और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केवल उद्योग स्थापित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों के लिए आधुनिक जीवनशैली, आवास और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने डेवलपर्स को परियोजना के कार्यान्वयन में और तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि आने वाले समय में उद्योगों की बढ़ती मांग को समय रहते पूरा किया जा सके।

हर्ष संघवी ने यह भी कहा कि धोलेरा में लगातार बढ़ रहे निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के कारण निकट भविष्य में रेडी-टू-मूव घरों और आधुनिक टाउनशिप की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि धोलेरा आने वाले वर्षों में देश के सबसे बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों में शामिल होगा, जहां रोजगार, निवेश और शहरी विकास के नए अवसर पैदा होंगे।

साइट विजिट के दौरान GAP ग्रुप के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को धोलेरा में तैयार किए जा रहे सबसे बड़े RCC राफ्ट फाउंडेशन निर्माण की जानकारी भी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्माण तकनीकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और बड़े पैमाने पर किए जा रहे इंजीनियरिंग कार्यों के जरिए क्षेत्र में आधुनिक और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में उन्नत निर्माण तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले मानकों का पालन किया जा रहा है, ताकि आने वाले दशकों तक यह परियोजना औद्योगिक और शहरी विकास की जरूरतों को पूरा कर सके।